भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2105

दिनांक 31.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाना

2105. श्री यूसुफ पठानः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत ने व्यापार, संपर्क–सुविधा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाने हेतु पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय चर्चा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान पड़ोसी देशों के साथ किए गए प्रमुख समझौतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने भारत की "नेबरहुड फर्स्ट" नीति के अंतर्गत कोई नई पहल शुरू की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके अपेक्षित लाभ क्या हैं?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) हाँ, सरकार पड़ोसी देशों के साथ व्यापार, संपर्क और सुरक्षा सहित आपसी हित के सभी मुद्दों पर नियमित रूप से बातचीत करती है। देश–वार विवरण संलग्न **अनुबंध I** में दिया गया है।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान पड़ोसी देशों के साथ किए गए प्रमुख समझौतों का विवरण **अनुबंध II** में दिया गया है।

(ग) हां, भारत की "पड़ोसी प्रथम" नीति के तहत सुरक्षा (पारंपरिक और गैर–पारंपरिक दोनों, समुद्री और साइबर सुरक्षा, जलवायु सुरक्षा, आपदा तैयारी, खाद्य सुरक्षा और मानव सुरक्षा सहित) को मजबूत करने और संपर्क (व्यापार, ऊर्जा, परिवहन, डिजिटल और लोगों से लोगों की संपर्क) बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई नई पहल शुरू की गई हैं; देशवार विवरण संलग्न **अनुबंध III** में दिया गया है।

अनुबंध I

व्यापार, संपर्क और सुरक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को मज़बूत करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ हाल ही में हुई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय चर्चाओं की सूची

(क) बांग्लादेश

(i) दिनांक 09 दिसंबर 2024 को विदेश कार्यालय परामर्श।

(ii) विदेश मंत्री ने 30 दिसंबर 2025 को बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए ढाका का दौरा किया, जब तत्कालीन बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी।

(iii) माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 17 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह के लिए बांग्लादेश का दौरा किया था।

(iv) बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने 7–9 अप्रैल 2026 के बीच भारत का दौरा किया और विदेश मंत्री, एनएसए और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के साथ बैठकें कीं।

(v) आपसी महत्व के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सुरक्षा और सीमा प्रबंधन, जल, व्यापार, संपर्क और विकास सहयोग से संबंधित संस्थागत द्विपक्षीय तंत्रों की तकनीकी बैठकें आयोजित की गईं।

(vi) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक में आयोजित छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। शिखर सम्मेलन के मौके पर बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफ़ेसर मुहम्मद यूनुस के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई।

(vii) क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति का आकलन करने और भविष्य के कदमों की रणनीति बनाने के लिए 6 मार्च 2025 को परिवहन संपर्क के लिए बिम्सटेक मास्टर प्लान की मध्यावधि समीक्षा आयोजित की गई थी। जुलाई 2025 में विशाखापत्तनम में आयोजित दूसरे बिम्सटेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव के दौरान, भारत सरकार ने बांग्लादेश और अन्य सदस्य देशों में कार्यान्वयन का समर्थन करने और तकनीकी क्षमता का निर्माण करने के लिए मुंबई में एक बिम्सटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट (बीएसएमएआरटीसी) की स्थापना की घोषणा की।

(viii) बिम्सटेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवीं बैठक 16 जुलाई 2026 को आयोजित की गई, जिसमें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रक्षा सलाहकार ने भी भाग लिया। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, परिवहन और व्यापार संपर्क, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संबंधों सहित क्षेत्रों में सदस्य देशों के बीच सहयोग की समीक्षा की गई।

(ix) बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने नवंबर 2025 में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक में भाग लिया, जहां सदस्य देशों ने क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की।

(x) ईएएम ने 17 फरवरी 2025 को ओमान में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन के मौके पर विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन के साथ एक बैठक की।

(ख) म्यांमार

(i) म्यांमार के राष्ट्रपति, मिन आंग ह्लाइंग की 30 मई से 03 जून 2026 तक भारत की यात्रा;

(ii) 08–11 अप्रैल 2026 के दौरान म्यांमार के राष्ट्रपति के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए विदेश राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह की म्यांमार यात्रा;

(iii) गृह सचिव की अध्यक्षता में 23वीं राष्ट्रीय स्तर की बैठक 07–08 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की गई;

(iv) वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों द्वारा दौरे – जिसमें रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह (25–26 सितंबर 2025), सीएनएस एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी (02–05 मई 2026) शामिल हैं;

(v) सुरक्षा और सीमा प्रबंधन, व्यापार, बिजली, नौवहन, पारंपरिक औषधियां, भारत फार्माकोपिया आदि क्षेत्रों में समय–समय पर कार्य स्तर की द्विपक्षीय बैठकें भी आयोजित की गई हैं।

(vi) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक में आयोजित छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। शिखर सम्मेलन के मौके पर तत्कालीन वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाइंग के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई;

(vii) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त से 01 सितंबर 2025 तक चीन के तियानजिन में आयोजित 25वें शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लिया। शिखर सम्मेलन के मौके पर तत्कालीन वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाइंग के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई;

(viii) राष्ट्रपति कार्यालय के मंत्री, टिन आंग सैन ने 16 जुलाई 2026 को आयोजित बिम्सटेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवीं बैठक में भाग लिया;

(ix) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्थायी सचिव, जीओएम ने एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लिया, जिसकी मेजबानी भारत ने की थी और फरवरी 2026 में आयोजित की गई थी;

(x) म्यांमार भी जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) में शामिल हो गया है।

(ग) भूटान

(i) व्यापार, वाणिज्य और पारगमन पर 2016 भारत–भूटान समझौते के नवीनीकरण/संशोधन के लिए आधिकारिक स्तर की वार्ता 18 मार्च 2026 को पहली तकनीकी स्तर की बैठक के साथ शुरू हुई।

(ii) सितंबर 2024 में व्यापार और उससे जुड़े मामलों को सुव्यवस्थित करने पर चर्चा के लिए वाणिज्य सचिव स्तर की वार्ता।

(iii) अप्रैल 2026 में सीमा शुल्क मामलों पर संयुक्त कार्य समूह की बैठक।

(iv) नवंबर 2025 में रेल–लिंक्स की स्थापना के लिए परियोजना संचालन समिति की बैठक।

(v) सीमा प्रबंधन और सुरक्षा पर थिम्फू में दिनांक16–17 अक्टूबर 2025 को भारत–भूटान सचिव स्तर की बैठक।

(vi) दिनांक24 सितंबर 2024 को रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान और असम राज्य सरकार के बीच सीमावर्ती जिलों के समन्वय की बैठक हुई।

(vii) रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के बीच सीमावर्ती जिलों की समन्वय बैठक 30–31 जनवरी 2025 को हुई।

(viii) भारत–भूटान सीमा कार्यों पर, सरकारी स्तर की बैठक (जीएलएम) दिनांक6–7 मार्च 2025 को हुई; और संयुक्त तकनीकी स्तर की बैठक (जेटीएलएम) दिनांक19–20 मई 2025 को हुई।

(ix) भूटान के गृह सचिव ने 16 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में बिम्सटेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की 5वीं बैठक में भाग लिया।

(घ) नेपाल

(i) दिनांक22 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में गृह सचिव स्तर की वार्ता (एचएसएलटी) आयोजित की गई।

(ii) सीमा कार्य समूह (बीडब्ल्यूजी) की बैठक दिनांक28–29 जुलाई 2025, नई दिल्ली।

(iii) नेपाल–भारत सहयोग पर विद्युत क्षेत्र में संयुक्त तकनीकी दल (जेटीटी) की 17वीं बैठक दिनांक3–4 नवंबर 2025 को पोखरा, नेपाल में आयोजित की गई।

(iv) दिनांक 4 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में 11वीं लाइन ऑफ़ क्रेडिट (एलओसी) समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

(v) राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एनपीए) परियोजना पर 5वीं संयुक्त परियोजना निगरानी समिति (जेपीएमसी), 1 दिसंबर 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित की गई।

(vi) पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र संबंधी भारत–नेपाल संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की 5वीं बैठक 8 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

(vii) 9वीं संयुक्त कृषि कार्य समूह (जेएडब्ल्यूजी) की बैठक 28–29 दिसंबर 2025 को काठमांडू में आयोजित की गई।

(viii) सर्वेक्षण अधिकारी समिति (एसओसी) की बैठक 2–4 फरवरी 2026 को काठमांडू में आयोजित की गई।

(ix) 17वीं भारत–नेपाल विद्युत आदान–प्रदान समिति (पीईसी) की बैठक 12–13 मार्च 2026 को पोखरा, नेपाल में आयोजित की गई।

(x) राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एनपीए) परियोजना पर छठी संयुक्त परियोजना निगरानी समिति (जेपीएमसी) 27 अप्रैल 2026 को वीसी मोड में आयोजित की गई।

(xi) कोसी और गंडक परियोजना संबंधी भारत–नेपाल संयुक्त समिति (जेसीकेजीपी) की 11वीं बैठक 30 अप्रैल–1 मई 2026 को काठमांडू में आयोजित की गई।

(xii) भारत और नेपाल के बीच नदियों में बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधियों पर भारत–नेपाल संयुक्त दल की दूसरी द्विपक्षीय बैठक 2 मई 2026 को काठमांडू में आयोजित की गई।

(xiii) नेपाल–भारत सहयोग में विद्युत क्षेत्र संबंधी संयुक्त तकनीकी दल (जेटीटी) की 18वीं बैठक 7–8 मई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

(xiv) रेल लिंकशेल्ड पर 10वीं परियोजना संचालन समिति (पीएससी) की बैठक 11 जून 2026 को काठमांडू में आयोजित की गई ।

(xv) रेल लिंक पर 8वीं संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठक 12 जून 2026 को काठमांडू में आयोजित की गई।

(xvi) विद्युत क्षेत्र में नेपाल–भारत सहयोग संबंधी संयुक्त कार्य समूह (जेडीडब्ल्यूजी) की 13वीं बैठक 14 जुलाई 2026 को पोखरा, नेपाल में आयोजित की गई।

(xvii) विद्युत क्षेत्र में नेपाल–भारत सहयोग पर संयुक्त संचालन समिति (जेएससी) की 13वीं बैठक 15 जुलाई 2026 को पोखरा, नेपाल में आयोजित की गई।

(ङ) श्रीलंका

(i) श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने दिसंबर 2024 में भारत की यात्रा की, जिसके दौरान 'साझा भविष्य के लिए भागीदारी को बढ़ावा देना' शीर्षक संबंधी संयुक्त वक्तव्य अपनाया गया;

(ii) प्रधानमंत्री ने 5–6 अप्रैल 2025 को श्रीलंका की यात्रा की। अन्य करारों के अलावा, दोनों पक्षों के बीच रक्षा सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए।

(iii) श्रीलंका के राष्ट्रपति महामहिम अनुरा कुमार दिसानायका ने फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की यात्रा की और प्रधानमंत्री के साथ भेंट की, जिसके दौरान संबंधित कनेक्टिविटी, व्यापार और आर्थिक संबंधों के विस्तार पर भी चर्चा की गई;

(iv) भारत के माननीय उपराष्ट्रपति ने 19–20 अप्रैल 2026 तक श्रीलंका की यात्रा की;

(v) चक्रवात दित्वा के मद्देनज़र विदेश मंत्री ने 23 दिसंबर 2025 को श्रीलंका की यात्रा की और पुनर्वास/पुनर्निर्माण के लिए 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की;

(vi) श्रीलंका के प्रधानमंत्री डॉ. हारिनी अमरासुरीया ने 16–18 अक्टूबर 2025 से भारत की यात्रा की;

(vii) भारतीय वायु सेना के वायु सेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने 19–21 मई 2026 तक श्रीलंका की यात्रा की;

(viii) भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने 7–8 जनवरी 2026 से श्रीलंका की यात्रा की;

(ix) भारत के नौसेना प्रमुख, एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने 22–25 सितंबर 2025 तक श्रीलंका की यात्रा की;

(x) वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल करने वाले आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग करार (ईटीसीए) को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत। अंतिम (14वां) दौर की वार्ता 24–26 जुलाई 2024 को आयोजित की गई थी। दोनों पक्ष बातचीत की शीघ्र बहाली के लिए कार्य कर रहे हैं;

(xi) नवीकरणीय ऊर्जा पर भारत–श्रीलंका संयुक्त कार्य समूह (जेडीडब्ल्यूजी) की दूसरी बैठक 23 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी;

(xii) 30 अक्टूबर 2025 को भारत–श्रीलंका पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन के कार्यान्वयन से संबंधित तौर–तरीकों पर चर्चा करने के लिए सचिव–स्तरीय एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई ; और

(xiii) रक्षा सचिव के नेतृत्व में 8वीं भारत–श्रीलंका रक्षा वार्ता 05 जून 2025 को कोलंबो में आयोजित की गई थी।

(च) मालदीव

(i) भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25–26 जुलाई 2025 से मालदीव की यात्रा की। व्यापार और अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई;

(ii) विदेश राज्य मंत्री, महामहिम अब्दुल्ला हमीद ने रायसीना संवाद में भाग लेने के लिए 4–8 मार्च 2026 से भारत की यात्रा की;।

(iii) मालदीव के आर्थिक विकास, परिवहन और व्यापार मंत्री महामहिम मोहम्मद सईद ने 07 जुलाई से 9 जुलाई 2026 तक भारत की यात्रा की;

(iv) होमलैंड, सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, महामहिम डॉ. मोहम्मद कीनानाथ ने एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन के लिए 17 से 21 फरवरी 2026 तक भारत की यात्रा की।

(v) मालदीव के अध्यक्ष, माननीय अब्दुल रहीम अब्दुल्ला 28वें राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन (सीएसपीओसी) में भाग लेने के लिए 13–18 जनवरी 2026 तक भारत की यात्रा की;

(vi) मालदीव की विदेश मंत्री सुश्री इरुथिशम एडम ने 12–14 मई 2026 से भारत की यात्रा की। उन्होंने विदेश मंत्री से मुलाकात की और उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के पूरे दायरे की समीक्षा की।

(vii) होमलैंड, सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट अब्दुल्ला फैरोश ने तीसरे भारत–मालदीव कांसुलर डायलॉग में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की;

(viii) 6 अक्टूबर 2025 को माले में रक्षा सचिव के नेतृत्व में छठी रक्षा सहयोग वार्ता आयोजित की गई थी; और

(ix) भारत और मालदीव ने 29 जुलाई 2026 को मालदीव में 9वीं संयुक्त स्टाफ वार्ता आयोजित की, जिसकी सह–अध्यक्षता एवीएम सुंदरमणि कृष्णन और ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद सलीम, कमांडेंट कोस्ट गार्ड ने की।

अनुबंध–II

पिछले दो वर्षों के दौरान पड़ोसी देशों के साथ हस्ताक्षरित प्रमुख करारों की सूची

श्री लंका

क्र. सं.	हस्ताक्षरित किए गए करार या समझौता ज्ञापन (एमओयू)
1	भारत सरकार के राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) तथा श्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर श्रीलंका इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (एसएलआईडीए) के बीच समझौता ज्ञापन
2	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचाव और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए श्रीलंका के लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार के बीच करार में संशोधन के लिए प्रोटोकॉल।
3	विद्युत के आयात/निर्यात के लिए एचवीडीसी इंटरकनेक्शन के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन
4	डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर लागू सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
5	त्रिंकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने में सहयोग के लिए भारत गणराज्य की सरकार, श्रीलंका के लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की सरकार और संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन
6	रक्षा सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन
7	पूर्वी प्रांत के लिए बहु–क्षेत्रीय अनुदान सहायता संबंधी समझौता ज्ञापन
8	स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन।
9	भारतीय फार्माकोपिया आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत गणराज्य की सरकार और राष्ट्रीय औषधि नियामक प्राधिकरण, श्रीलंका के लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच

	फार्माकोपिया सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन।
10	भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता के माध्यम से श्रीलंका में उच्च प्रभाव वाले सामुदायिक विकास परियोजनाओं (एचआईसीडीपी) के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन (5 वर्षों के लिए बढ़ाई गई)

मालदीव

क्र.सं.	**हस्ताक्षरित करार या समझौता ज्ञापन**
1	मुद्रा विनिमय करार
2	भारत गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और मालदीव गणराज्य के नेशनल कॉलेज ऑफ पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट के बीच समझौता ज्ञापन
3	भ्रष्टाचार को रोकने और उससे निपटने में द्विपक्षीय सहयोग के लिए भारत के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और मालदीव के भ्रष्टाचार निवारण आयोग के बीच समझौता ज्ञापन
4	मालदीव के न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर भारत के राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और मालदीव के न्यायिक सेवा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण
5	खेल और युवा मामलों में सहयोग पर भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण
6	मालदीव को 4,850 करोड़ रूपए की ऋण सहायता का करार
7	भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित ऋण सहायता पर मालदीव के वार्षिक ऋण पुनर्भुगतान दायित्वों को कम करने पर संशोधनात्मक करार
8	भारत–मालदीव मुक्त व्यापार करार **की** संदर्भ शर्तें
9	मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन
10	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और पर्यटन तथा पर्यावरण

क्र.सं.	हस्ताक्षरित करार या समझौता ज्ञापन
	मंत्रालय के मालदीव मौसम विज्ञान सेवा के बीच समझौता ज्ञापन
11	डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्तर पर लागू किए गए सफल डिजिटल समाधानों के आदान–प्रदान के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय तथा मालदीव के गृह सुरक्षा और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन
12	मालदीव द्वारा भारतीय भेषजसंहिता (आई पी) की मान्यता पर समझौता ज्ञापन
13	मालदीव में यूपाआई को लेकर भारत के एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड (एनआईपीएल) और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (एम एम ए) के बीच नेटवर्क–टू–नेटवर्क करार

म्यांमार

क्र.सं.	हस्ताक्षरित करार या समझौता ज्ञापन
1	उड़द और तुअर (अरहर) के व्यापार के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन, जिसे वित्तीय वर्ष 2030–2031 तक पांच वर्षों के लिए बढ़ाया गया, मार्च 2026 में हस्ताक्षरित किया गया था
2	नेपिडॉ स्टेट एकेडमी को प्रयोगशाला उपकरण और उपकरण की आपूर्ति पर, फरवरी 2026 में हस्ताक्षरित किया गया समझौता ज्ञापन
3	डिजिटल पहचान के क्षेत्र में सहयोग पर, जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित किया गया समझौता ज्ञापन
4	सरसोबेइकमैन साहित्यिक भवन के निर्माण पर मार्च 2024 में हस्ताक्षरित किया समझौता ज्ञापन

नेपाल

क्र.सं.	हस्ताक्षरित करार या समझौता ज्ञापन
1	वर्ष2023 में हस्ताक्षरित जी2जी समझौता ज्ञापन में परिकल्पित परियोजनाओं के निष्पादन के लिए

क्र.सं.	हस्ताक्षरित करार या समझौता ज्ञापन
	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इंडियन ऑयल) और नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन के बीच बी टू बी फ्रेमवर्क करार
2	अपशिष्ट प्रबंधन सहित पानी, स्वच्छता और साफ़–सफ़ाई क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन
3	न्यायिक सहयोग को विकसित करने, बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय और नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के बीच समझौता ज्ञापन
4	भारत और नेपाल के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन
5	भारत और नेपाल के बीच पारगमन संधि के प्रोटोकॉल में संशोधन करने वाला विनिमय–पत्र
6	व्यापार सुविधा और सीमा शुल्क नियंत्रण के लिए माल के निर्यात की पूर्व–आगमन जानकारी के आदान–प्रदान में सहयोग हेतु सीबीआईसी (भारत) और सीमा शुल्क विभाग (नेपाल) के बीच समझौता ज्ञापन
7	आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर करार
8	जैव विविधता संरक्षण पर भारत और नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन
9	"वॉइस फर्स्ट" भाषा अनुवाद मंच के लिए राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना के सह–निर्माण हेतु डिजिटल इंडिया भाषिणी और काठमांडू विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन

भूटान

क्र.सं.	हस्ताक्षरित करार या समझौता ज्ञापन

1	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार) और ऊर्जा विभाग (ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय, भूटान की शाही सरकार) के बीच रिएक्टिव ऊर्जा लेखांकन की कार्यप्रणाली पर करार
2	पुनात्सांगछु–II जलविद्युत परियोजना के संबंध में 30 अप्रैल 2010 को भारत गणराज्य की सरकार और भूटान की शाही सरकार के बीच हुए करार का प्रोटोकॉल (टैरिफ प्रोटोकॉल)
3	मूलधन और ब्याज के कुल ऋण भुगतान अनुसूची पर भूटान में मांगदेछु जलविद्युत परियोजना के संबंध में 30 अप्रैल 2010 को हस्ताक्षरित करार का प्रोटोकॉल
4	डाक क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भूटान की शाही सरकार के अवसंरचना और परिवहन मंत्रालय तथा भारत सरकार के संचार मंत्रालय के डाक विभाग के बीच समझौता ज्ञापन
5	नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और भूटान की शाही सरकार के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन
6	स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भूटान की शाही सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन
7	संस्थागत जुड़ाव के निर्माण पर पेमा सचिवालय (भूटान) और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (एनआईएमएचएएनएस, भारत) के बीच समझौता ज्ञापन
8	भारत और भूटान के बीच रेल लिंक स्थापित करने के लिए भारत सरकार और भूटान की शाही सरकार के बीच समझौता ज्ञापन
9	कृषि, पशुधन और संबद्ध क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग पर भारत गणराज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और भूटान की शाही सरकार के कृषि और पशुधन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन
10	न्यायिक शिक्षा और पारस्परिक आदान–प्रदान में सहयोग पर भूटान नेशनल लीगल इंस्टीट्यूट और नेशनल जुडिशल एकेडमी (भोपाल) के बीच समझौता ज्ञापन

11	न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में भूटान के सर्वोच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बीच समझौता ज्ञापन
12	भारत से भूटान को पेट्रोलियम, तेल, स्नेहक (पीओएल) और संबंधित उत्पादों की सामान्य आपूर्ति पर भारत गणराज्य की सरकार और भूटान की शाही सरकार के बीच समझौता ज्ञापन
13	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा भूटान खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण द्वारा किए गए आधिकारिक नियंत्रण की मान्यता का करार
14	ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण उपायों के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन
15	खेल और युवा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन
16	संदर्भ मानक साझा करने, भेषजसंहिता, सतर्कता और औषधीय उत्पादों के परीक्षण से संबंधित सहयोग पर समझौता ज्ञापन
17	अंतरिक्ष सहयोग पर संयुक्त कार्य योजना
18	भारत के नेशनल नॉलेज नेटवर्क और भूटान के ड्रुक रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क के बीच पीयरिंग व्यवस्था पर समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण
19	ग्यालसंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऋण के संबंध में भारत सरकार और भूटान की शाही सरकार के बीच समझौता ज्ञापन

अनुबंध –III

भारत की पड़ोस प्रथम नीति के तहत शुरू की गई नई पहलें

श्रीलंका

श्रीलंका में चक्रवात दितवाह के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए लगभग 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज (एस.ई.पी.)।

मालदीव

मालदीव में यू.पी.आई. के संदर्भ में एन.पी.सी.आई. और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच नेटवर्क–टू–नेटवर्क समझौते के माध्यम से वित्तीय संपर्क का विस्तार करना तथा मालदीव में मछुआरों, स्वास्थ्य और आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर संयुक्त कार्य समूह (जे.डब्ल्यू.जी.) की स्थापना करना।

अफगानिस्तान

दोनों देशों के बीच हवाई मालवाहक गलियारा, संयुक्त कार्य समूह और संयुक्त वाणिज्य मंडल सहित कई पहलें शुरू की गई हैं।

म्यांमार

पड़ोस प्रथम नीति के तहत, भारत ने व्यापक विकासात्मक सहायता के माध्यम से म्यांमार के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में कार्य किया है। हाल ही में, मेकांग–गंगा सहयोग के तहत, म्यांमार के नागरिकों के लिए आई.सी.सी.आर. छात्रवृत्ति सीटों की संख्या को सालाना 36 से बढ़ाकर 100 कर दिया गया। इसके अलावा, एक जिम्मेदार पड़ोसी और प्रतिबद्ध क्षेत्रीय भागीदार के रूप में, भारत संकट के समय म्यांमार के लिए सबसे पहला मददगार रहा है। मार्च 2025 में म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के बाद, भारत ने मानवीय सहायता और राहत प्रदान करने के लिए 'ऑपरेशन ब्रह्मा' की शुरुआत की।

बांग्लादेश

1.अक्टूबर 2024 में आई.सी.पी. पेट्रापोल में दूसरे कार्गो ट्रेड गेट के उद्घाटन के माध्यम से बांग्लादेश के साथ व्यापार और संपर्क को बढ़ावा देना।

2.भारतीय ग्रिड का उपयोग करके नेपाल से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लिए नेपाल, बांग्लादेश और भारत के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते के साथ ऊर्जा क्षेत्र में उप–क्षेत्रीय संपर्क की भी शुरुआत की गई है। इस व्यवस्था के तहत पहला निर्यात नवंबर 2024 में किया गया था।

नेपाल

(i) दीर्घकालिक बिजली व्यापार: वर्ष 2024 में हस्ताक्षर किए गए दीर्घकालिक बिजली व्यापार समझौते के तहत अगले एक दशक में नेपाल से भारत को 10,000 मेगावाट तक बिजली निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ii) सीमा पार डिजिटल भुगतान: भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यू.पी.आई.) और नेपाल के राष्ट्रीय भुगतान इंटरफेस (एन.पी.आई.) के बीच पीयर–टू–पीयर (पी2पी) लिंक की शुरुआत 6 जून 2026 को की गई। यह भारत और नेपाल के बीच सीमा पार व्यक्तिगत धन प्रेषण को सुविधाजनक बनाएगा।

(iii) आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता समझौता (एम.एल.ए.ए.): इस समझौते पर फरवरी 2026 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता सीमा पार अपराधों से संबंधित जांच, अभियोजन और न्यायिक कार्यवाही की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एक संस्थागत कानूनी अवसंरचना प्रदान करके भारत और नेपाल के लोगों को लाभान्वित करेगा।

(IV) भारत–नेपाल स्टार्टअप पार्टनरशिप नेटवर्क (इन–स्पैन) कार्यक्रम:

इन–स्पैन का उद्देश्य सीमा पार नवाचार को गति देना, निवेश संबंधों को बढ़ावा देना और भारत तथा नेपाल के बीच स्थायी उद्यमशीलता साझेदारी का निर्माण करना है। इस कार्यक्रम के तहत, नेपाल के 24 स्टार्टअप्स ने दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के दौरान आई.आई.टी. मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन में आठ सप्ताह के प्रशिक्षण सह इंक्यूबेशन कार्यक्रम में भाग लिया। इन–स्पैन के दूसरे कोहोर्ट में नेपाल के 25 स्टार्टअप्स की भागीदारी देखी गई, जो वर्तमान में दिनांक 31 जुलाई 2026 तक आई.आई.टी. मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

V. भारत और नेपाल के बीच पारगमन संधि के प्रोटोकॉल में संशोधन करने वाला विनिमय पत्र (एल.ओ.ई.): नवंबर 2025 में भारत–नेपाल पारगमन संधि के प्रोटोकॉल में संशोधन करने वाले विनिमय पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद, 20 जुलाई 2026 को पहली व्यावसायिक खेप कोलकाता बंदरगाह से जोगबनी स्थित भारतीय सीमा शुल्क यार्ड के रास्ते नेपाल सीमा शुल्क यार्ड, विराटनगर पहुंची। यह सीमा पार कार्गो ट्रेन सेवा लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और भारत–नेपाल व्यापार को और बढ़ावा देने में मदद करेगी।

(vi) "वॉइस फर्स्ट" भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म के लिए राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना के सह–निर्माण हेतु डिजिटल इंडिया भाषिणी और काठमांडू विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन दिनांक 6 जून 2026 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौता ज्ञापन को लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने और भाषाई विरासत को संरक्षित करने की एक पहल के रूप में परिकल्पित किया गया है।

भूटान

(i) भारत और भूटान के बीच रेल संपर्कों की स्थापना: भारत और भूटान के बीच दो सीमा पार रेल संपर्कों, अर्थात बनाहाट–सामत्से और कोकराझार–गेलेफू का निर्माण कार्य किया जा रहा है। ये रेल संपर्क सीमा पार संपर्क को मजबूत करेंगे तथा व्यापार और जन–सामान्य के बीच संबंधों को बढ़ावा देंगे।

(ii) भारत और भूटान के बीच आध्यात्मिक बौद्ध संबंधों को सुदृढ़ करना: बिहार के राजगीर में रॉयल भूटान मंदिर की प्राण–प्रतिष्ठा सितंबर 2025 में की गई थी। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में तीसरे भूटानी मंदिर और मठ के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की है। यह पहल भारत और भूटान के बीच सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत संबंधों को मजबूत करेगी और इससे पर्यटन तथा आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि होने की संभावना है।

(iii) भूटान में भारत के भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम) एप्लिकेशन के शुभारंभ के माध्यम से डिजिटल भुगतान संपर्क को बढ़ावा देना: यह पहल भूटान के साथ आर्थिक सहयोग का विस्तार करेगी और सीमा पार भुगतानों में सहजता के माध्यम से पर्यटकों, छात्रों, व्यापारियों आदि को सुविधा प्रदान करेगी।

(iv) दररंगा, असम में एकीकृत जांच चौकी (आई.सी.पी.) की स्थापना: इस आई.सी.पी. का उद्घाटन नवंबर 2024 में किया गया था। यह भारत–भूटान सीमा पर तीसरे देश के नागरिकों के प्रवेश और निकास को सुगम बनाएगा तथा द्विपक्षीय व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगा।

(v) भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना (एफ.वाई.पी.) को सहायता: भारत सरकार ने भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना (2024–2029) के लिए 10,000 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्रतिबद्ध की है। भारत सरकार की यह सहायता भूटान के विकास प्रयासों में योगदान देगी और भारत–भूटान विकास साझेदारी को गहरा करेगी, जो भूटान के साथ द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

*****